भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 4603

20 मार्च, 2026 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

एनएससीईएम के अंतर्गत जनजातीय लोगों की जांच

4603. श्री विजय कुमार दूबेः
श्री बलभद्र माझीः
श्री राजेश रंजनः
श्रीमती अनिता नागरसिंह चौहानः
श्री जसवंतसिंह सुमनभाई भाभोरः
श्रीमती हिमाद्री सिंहः
श्री भोजराज नागः
श्री कौशलेन्द्र कुमारः
श्रीमती स्मिता उदय वाघः
डॉ. निशिकान्त दुबेः
श्री शिवमंगल सिंह तोमरः
श्री चिन्तामणि महाराजः

क्या **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देश में विशेषकर गुजरात, मध्य प्रदेश, ओडिशा, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र राज्यों में और दाहोद, नबरंगपुर और शहडोल संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन की शुरुआत के बाद से कितने जनजातीय लोगों की जांच की गई है और फरवरी, 2026 तक कितने जेनेटिक स्टेटस कार्ड जारी किए गए/वितरित किए गए हैं;

(ख) उक्त मिशन के अंतर्गत किन-किन जिलों में जांच की गई है और अब तक जिला-वार कुल कितने व्यक्तियों की जांच की गई है;

(ग) क्या सरकार ने अनुसूचित जनजाति की अधिक आबादी वाले जिलों में सफलता प्राप्त की है और यदि हां, तो तत्संबंधी जिला-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) रतलाम लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत रतलाम, झाबुआ और अलीराजपुर जिलों सहित जिला-वार कितने व्यक्तियों की जांच की गई है और कितने जेनेटिक स्टेटस कार्ड जारी किए गए हैं;

(ङ) मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और झारखंड जैसे उच्च व्याप्तता वाले राज्यों में विवाहपूर्व परामर्श, आनुवांशिक परीक्षण और विशिष्ट उपचार केन्द्रों के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के साथ समन्वय तंत्र का ब्यौरा क्या है;

(च) क्या दाहोद लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र में विशेष परामर्श और उपचार केन्द्र स्थापित किए गए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(छ) जनजातीय क्षेत्रों, विशेषकर बस्तर डिवीज़न और नबरंगपुर लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र में कुपोषण और रक्ताल्पता से निपटने के लिए स्थानीय पोषक पूरक आहार पर अनुसंधान के लिए कितना बजट आवंटन और व्यय किया गया है; और

(ज) क्या जनजातीय बहुल क्षेत्रों में समर्पित सिकल सेल क्लीनिक, परीक्षण प्रयोगशालाएं और टेलीमेडिसिन सहायता शुरू की गई है?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क) से (ज): राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन (एनएससीएईएम) के अंतर्गत, प्रभावित 17 आदिवासी राज्यों में जिला अस्पतालों (डीएच) से लेकर आयुष्मान आरोग्य मंदिर (एएएम) स्तर तक सभी स्वास्थ्य सुविधा केंद्रों में 0-40 वर्ष के लक्षित आयु वर्ग में सिकल सेल रोग (एससीडी) के निदान के लिए जांच की जाती है।

एससीडी पोर्टल पर राज्यों द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, गुजरात, मध्य प्रदेश, ओडिशा, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र सहित देश के जनजातीय बहुल क्षेत्रों में 6.97 करोड़ से अधिक जांच की जा चुकी है। दिनांक 16.03.2026 तक की स्थिति के अनुसार, राज्यवार जनजातीय आबादी में की गई जांच की संख्या और वितरित किए गए जेनेटिक स्टेटस कार्डों की संख्या **अनुलग्नक** में दी गई है।

दाहोद, नबरंगपुर, शहडोल और रतलाम लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों के जिलों में दिनांक 16.03.2026 तक की स्थिति के अनुसार जांच किए गए लोगों की संख्या और वितरित किए गए जेनेटिक स्टेटस कार्डों की संख्या इस प्रकार है:

क्र.सं.	जिले का नाम	**जांच किए गए लोगों की संख्या**	**वितरित किए गए जेनेटिक स्टेटस कार्डों की संख्या**
1.	दाहोद	15,19,856	15,21,371
2.	नबरंगपुर	3,30,369	1,86,923
3.	शहडोल	6,06,485	5,46,243
4.	रतलाम	2,57,829	2,22,814
5.	झाबुआ	8,55,094	8,25,700
6.	अलीराजपुर	6,68,684	6,35,549

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने विभिन्न राज्यों में जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा वित्त पोषित सिकल सेल रोग पर उत्कृष्टता केंद्रों (सीओई) की स्थापना के लिए लागत मानदंड तैयार किए हैं। 15 राज्यों में स्थित 17 उत्कृष्टता केंद्रों को जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा अनुमोदित किया जा चुका है।

एएएम उप स्वास्थ्य केंद्रों (एसएचसी) और एएएम पीएचसी के माध्यम से सिकल सेल रोग से पीड़ित रोगियों को उनके जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए निम्नलिखित सेवाएं/सुविधाएं प्रदान की जाती हैं:

- रोगग्रस्त व्यक्तियों की नियमित अंतराल पर अनुवर्ती जांच।
- जीवनशैली प्रबंधन, विवाह पूर्व और गर्भावस्था संबंधी निर्णयों के बारे में परामर्श।
- फोलिक एसिड की गोलियों के वितरण के माध्यम से पोषण संबंधी सहायता।
- योग और स्वास्थ्य सत्रों का संचालन।
- संकटकालीन लक्षणों का प्रबंधन और उच्च स्तरीय चिकित्सा सुविधाओं के लिए रेफरल।

सरकार राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के तहत प्रजनन, मातृ एवं नवजात शिशु, किशोर स्वास्थ्य और पोषण (आरएमएनसीएएच+एन) रणनीति के माध्यम से, देश की जनजातीय आबादी, जिसमें बस्तर डिवीजन और नबरंगपुर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र शामिल हैं, में कुपोषण और एनीमिया को कम करने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है, जिसमें जननी सुरक्षा योजना (जेएसवाई), जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम (जेएसएसके), प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान (पीएमएसएमए), विस्तारित पीएमएसएमए, लक्ष्य, सुरक्षित मातृत्व आश्वासन (सुमन), सुविधा आधारित नवजात देखभाल, कंगारू मदर केयर (केएमसी), माताओं का पूर्ण स्नेह (एमएए), एनीमिया मुक्त भारत (एएमबी), घर आधारित नवजात शिशु देखभाल (एचबीएनसी) और छोटे बच्चों की घर-आधारित देखभाल (एचबीवाईसी) कार्यक्रम, मासिक ग्राम स्वास्थ्य, स्वच्छता और पोषण दिवस (वीएचएसएनडी), नियमित आउटरीच गतिविधियां, जनजातीय बस्तियों में आशाकर्मी और अन्य फ्रंटलाइन कार्यकर्ताओं द्वारा स्वास्थ्य शिक्षा और स्क्रीनिंग जैसी स्कीमों के माध्यम से प्रसवपूर्व देखभाल, संस्थागत प्रसव, प्रसवोत्तर देखभाल और परिवार नियोजन सेवाओं, संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित किया जाता है।

मिशन पोषण 2.0 के तहत, सरकार मातृ पोषण, शिशु एवं बाल पोषण मानकों, गंभीर तीव्र कुपोषण (एसएएम)/मध्यम तीव्र कुपोषण (एमएएम) के उपचार और आयुष पद्धतियों के माध्यम से स्वास्थ्य पर ध्यान केंद्रित करती है ताकि दुर्बलता, बौनापन, एनीमिया और अल्प वजन की व्यापकता को कम किया जा सके। आंगनवाड़ी केंद्रों में 6 महीने से 6 वर्ष की आयु के बच्चों, गर्भवती महिलाओं, स्तनपान कराने वाली माताओं और किशोरियों को पोषण मानकों के अनुसार पूरक पोषण प्रदान किया जाता है, जो आहार वैविध्यता के सिद्धांतों पर आधारित है और इसमें गुणवत्तापूर्ण प्रोटीन, स्वस्थ वसा और सूक्ष्म पोषक तत्व प्रदान किया जाता है।

हैल्थ डायनेमिक्स ऑफ इंडिया (एचडीआई) (अवसंरचना एवं मानव संसाधन) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा रिपोर्ट किए गए स्वास्थ्य सेवा प्रशासनिक आंकड़ों पर आधारित एक वार्षिक प्रकाशन है। देश के जनजातीय बहुल क्षेत्रों में राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों के अनुसार, अस्वाभाविक रोगों की जांच और उपचार की सुविधा उपलब्ध कराने वाली स्वास्थ्य सुविधा केंद्रों का विवरण एचडीआई 2022-23 के निम्नलिखित लिंक पर देखा जा सकता है:

https://mohfw.gov.in/sites/default/files/Health%20Dynamics%20of%20India%20%28Infrastructure%20%26%20Human%20Resources%29%202022-23_RE%20%281%29.pdf

देश भर में, जनजातीय बहुल क्षेत्रों सहित, सभी कार्यरत एएएम (प्राथमिक चिकित्सा केंद्र) में उपलब्ध टेलीकंसल्टेशन सेवाओं से लोगों को अपने घरों के पास ही एससीडी के लिए विशेषज्ञ सेवाओं तक पहुंचने में मदद मिलती है। इससे शारीरिक पहुंच संबंधी चिंताओं, सेवा प्रदाताओं की कमी और निरंतर देखभाल की सुविधा संबंधी चिंताओं का समाधान होता है। दिनांक 28.02.2026 तक एएएम में आयोजित कुल टेलीकंसल्टेशन की संख्या 44.08 करोड़ है।

दिनांक 20 मार्च, 2026 को लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 4603 के भाग (क) से (ज) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक

अनुलग्नक

दिनांक 16.03.2026 तक की स्थिति के अनुसार जांच की गई जनजातीय आबादी और वितरित किए गए जेनेटिक स्टेटस कार्डों की संख्या।

क्र.सं.	**राज्य का नाम**	**जांच किए गए लोगों की संख्या**	**वितरित किए गए जेनेटिक स्टेटस कार्डों की संख्या**
1	छत्तीसगढ़	1,73,52,532	1,02,91,526
2	मध्य प्रदेश	1,30,97,122	1,13,62,256
3	महाराष्ट्र	1,00,33,422	25,45,708
4	गुजरात	80,23,780	79,35,802
5	ओडिशा	62,71,477	33,13,308
6	राजस्थान	37,06,695	17,11,992
7	झारखंड	27,88,493	2,968
8	पश्चिम बंगाल	25,00,170	394
9	आंध्र प्रदेश	14,89,997	4,78,195
10	असम	11,82,605	1,53,858
11	तेलंगाना	11,37,233	5,41,261
12	उत्तर प्रदेश	7,64,871	4,41,716
13	तमिलनाडु	4,51,564	4,06,510
14	कर्नाटक	3,57,266	4,244
15	बिहार	2,40,335	63
16	उत्तराखंड	1,53,670	1,51,508
17	केरल	1,77,959	23,029
	कुल	**6,97,29,191**	**3,93,64,338**

*****